Effects of Public Expenditure

सार्वजनिक व्यय का अर्थ सरकार द्वारा किए गए खर्च से है। सार्वजनिक व्यय न केवल एक सरकारी प्रक्रिया है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति करना है।

Adam Smith सरकार की क्रियाओं को निम्नतम स्तर पर रखना चाहते थे। उनके अनुसार "State should least interfere in activities. There should be minimum activities of state. Justice, Police and army."

किन्तु आजकल सरकार की क्रियाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। Wagner महोदय ने "Law of increasing public expenditure" स्थापित किया है जिसके अनुसार आज के कल्याणकारी राज्यों में सार्वजनिक व्यय बढ़ते हुए दर से लगातार बढ़ता है। Wagner महोदय के विचार से आज अधिकांश लोग सहमत हैं। Wagner ने इसे निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट किया।

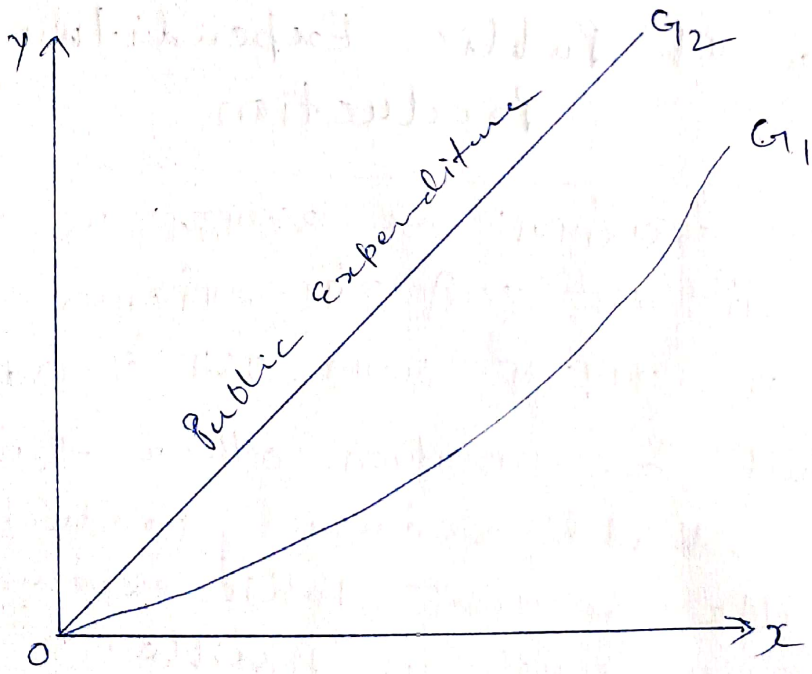

हालांकि "Wiseman Peacock" के अनुसार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है किन्तु लगातार नहीं। अचानक

प्राकृतिक या मानवकृत समस्याओं के कारण सार्वजनिक व्यय में एक उछाल हो जाता है। इसलिए सार्वजनिक व्यय की रेखा continious नहीं होती है बल्कि Discontinious होती है जैसा कि नीचे के चित्र में प्रदर्शित है—

सार्वजनिक व्यय का प्रभाव अर्थव्यवस्था के उत्पादन वितरण एवं रोजगार सभी क्षेत्रों पर पड़ता है।

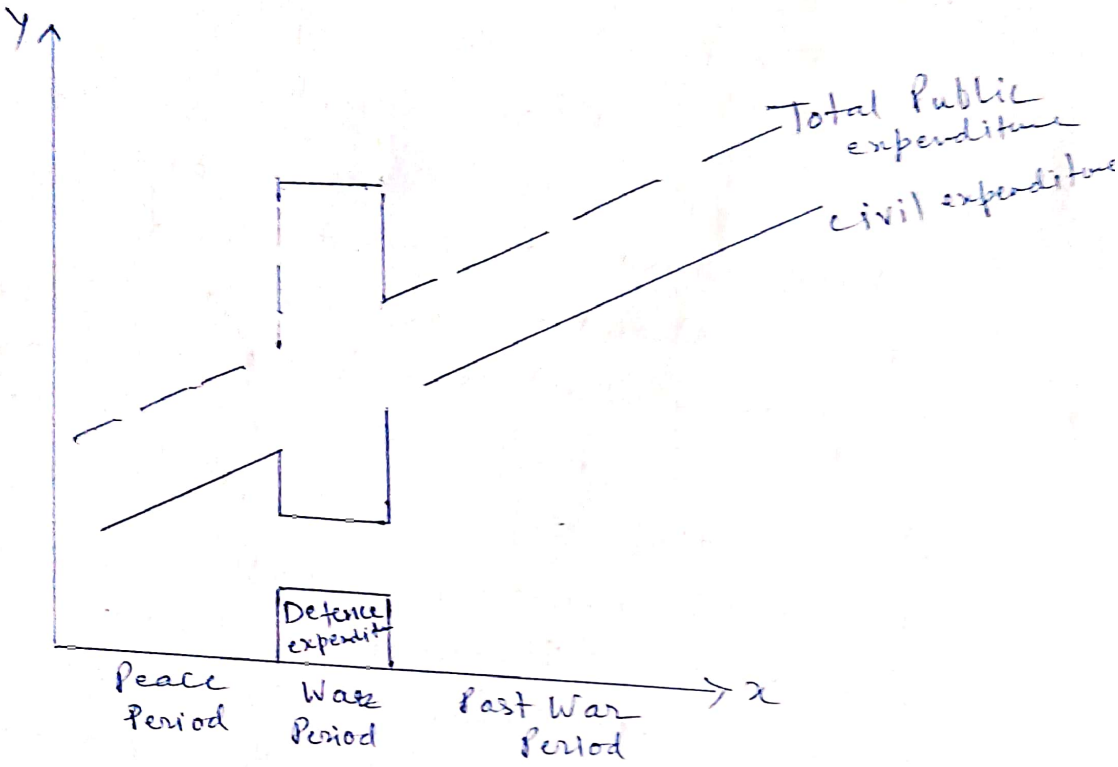

Effects of Public Expenditure on Production

एक ओर करारोपण का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। Dalton के शब्दों में " Just as taxation other things being equal, should reduced production as little as possible so that Public expenditure should increase as much as Possible."

Dalton ने सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर पड़ने

वाले प्रभाव को निम्नलिखित तत्वों के आधार पर विश्लेषण किया है —

1. Effect on ability to work, save and interest (कार्य करने, बचत करने व विनियोग करने की योग्यता पर प्रभाव)

कार्य करने, बचत करने की योग्यता का सम्बन्ध मुख्य रूप से रोजगार के स्तर से है। यदि सार्वजनिक व्यय के प्रभाव से देश में रोजगार पर अनुकूल प्रभाव होता है तो इससे उत्पादन बढ़ेगा अन्यथा इसके विपरीत प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तियों की कार्य करने, बचत करने की योग्यता में वृद्धि अनेक प्रकार से की जा सकती है जैसे - पेन्शन आवास योजना, बीमारी बीमा, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं पर किया गया सरकारी व्यय। इन कार्यों से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है और वे अधिक अच्छी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। उपभोग बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होगी और फिर रोजगार के साथ साथ आय स्तर में वृद्धि होगी जिससे बचत बढ़ेगी। बचत के बढ़ने से पूंजी निर्माण होगा और विनियोग बढ़ेगा। इसप्रकार की आर्थिक क्रिया से आर्थिक विकास का चक्र चलता रहेगा और अन्ततः उत्पादन का स्तर बढ़ेगा।

लेकिन यदि सरकार निर्धनों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो वे लोग इस सहायता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं यदि वे सरकार से प्राप्त राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा व पौष्टिक भोजन

पर व्यय न करके आराम व मुद्रा ... करने लगेगी।
करने लगे तो समाज की कार्यक्षमता घटेगी।
इसलिए राज्य इस प्रकार का प्रबन्ध करती है कि समाज के निर्धन वर्ग को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की अपेक्षा अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

सरकारी व्यय से अल्पकाल में तो हो सकता है कि निर्धनों को आलसी बना दे लेकिन दीर्घकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सम्बन्धी सुविधा पाकर निर्धन समाज भी शक्तिशाली समाज के रूप में उभरने की चेष्टा करेगा। जिससे देश का उत्पादन बढ़ेगा।

सरकारी व्यय से बचत करने की शक्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल में आर्थिक विकास के साथ यदि नियन्त्रण न लगाया जाय तो मूल्य स्तर में वृद्धि होने से व्यय और व्यय बराबर हो जाते हैं और बचत हतोत्साहित होने लगती है। अतः सोच समझकर किया जाने वाला सार्वजनिक व्यय ही कार्य करने व बचत करने की शक्तियों में वृद्धि करता है।

2. Effect on the desire to work save and investment

(कार्य करने, बचत करने व विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव)

सरकार प्रायः दो प्रकार का व्यय करती है। पहला वर्तमान योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय तथा दूसरा भविष्य सम्बन्धी योजनाओं पर किया जाने वाला

व्यय। वर्तमान योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय
से कार्य करने बचत करने तथा निवेश करने की इच्छा
में वृद्धि होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उत्तरोत्तर अपनी
स्थिति में सुधार लाना चाहता है। दूसरी ओर अगर ~~स्वास्थ्य~~
सरकार भविष्य सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय करती है
तो भविष्य की निश्चिन्तता के कारण काम करने, बचत
करने की इच्छा घटने लगेगी। फलतः उत्पादन घटेगा।
किन्तु यह विचार सही नहीं है। USA और
U.K में सामाजिक सुरक्षा बहुत ही अधिक मात्रा में
व्यक्तियों को उपलब्ध है किन्तु इसका उत्पादन पर
अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगर सरकार की नीति ऐसी
हो कि भविष्य में व्यक्तियों को उनके बचत पर पर्याप्त
मात्रा में मुनाफा मिलेगा। सार्वजनिक व्यय से अगर व्यक्तियों
का भविष्य सुरक्षित है तब हर देश में व्यक्तियों के
काम करने, बचत करने तथा विनियोग करने की इच्छा
में वृद्धि होगी।

3. Effect on Diversion of Resources
आर्थिक साधनों के हस्तान्तरण पर प्रभाव

सार्वजनिक व्यय का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन
पड़ पड़ता है। आर्थिक साधनों का हस्तान्तरण दो
प्रकार से होता है —

ⓐ प्रत्यक्ष हस्तान्तरण
ⓑ परोक्ष हस्तान्तरण

प्रत्यक्ष हस्तान्तरण में सरकार व्यक्तियों
की बचतों को अपने माध्यम से स्वयं ऐसे कार्यों को
करती है जिन कार्यों का संचालन व्यक्ति स्वयं नहीं कर
सकता, जबकि ये कार्य व्यक्तियों के लिए अत्यन्त

आवश्यक होता है। जैसे - जल की व्यवस्था, सिंचाई योजनाएँ, सड़क, रेल, पुलिस, सेना व न्यायालयों का किया जानेवाला व्यय।

परोक्ष हस्तान्तरण से अभिप्राय यह है कि फिर सरकार व्यक्तियों की व्यय को स्वयं प्राप्त नहीं करती और न कोई योजना बनाती है बल्कि वह एकप्रकार का वातावरण देकर व्यक्तियों को निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकती है। जैसे यातायात के साधनों को गाँवों तक ले जाने का अभिप्राय है कि लोग अपनी उत्पादित वस्तुओं को बाजार में ले जाकर बेचें, इसीप्रकार विद्युत शक्ति का विकास कर स्वयं ही छोटे मोटे उद्योगों को विकसित करना होता है।

सार्वजनिक व्यय से Social over head का निर्माण किया जाता है जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन आदि आता है। इससे सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि होती है जिससे व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। और उसका उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

सार्वजनिक व्यय से विज्ञान एवं तकनीक में परिवर्तन लाकर उत्पादन सम्भावना रेखा को ऊपर की ओर shift किया जा सकता है —

Scanned with OKEN Scanner

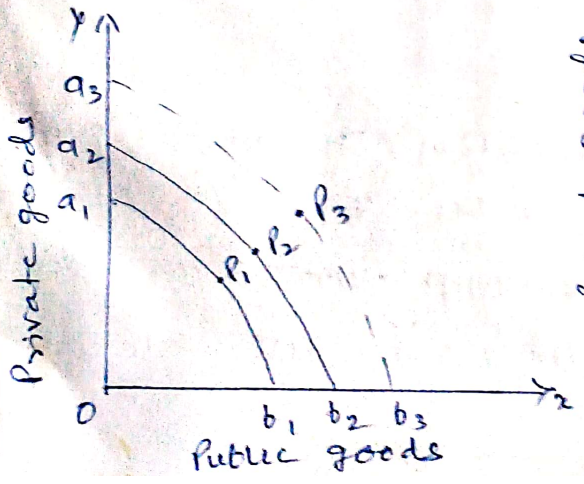

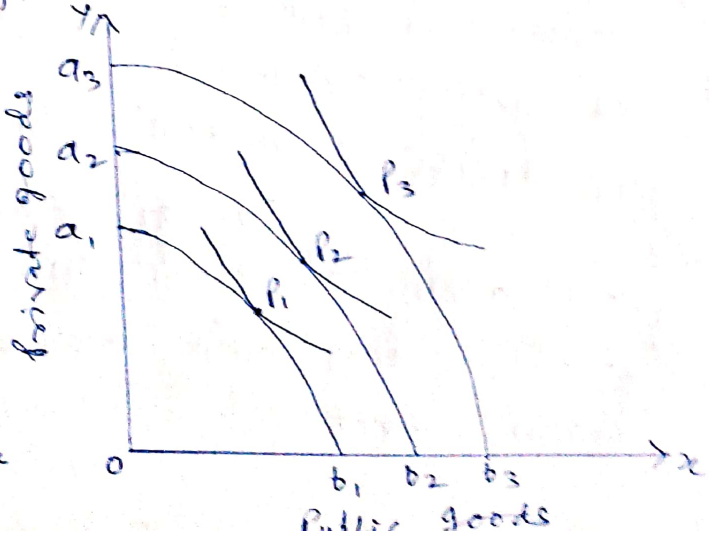

सार्वजनिक व्यय से Production possibilities curve ऊपर की ओर shift होता है जिसके फलस्वरूप उत्पादन संतुलन बिन्दु भी P_1 से ऊपर उठकर P_2 तथा P_3 हो जाती है।

Dalton ने सार्वजनिक व्यय ΔG के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्न चित्र से प्रदर्शित किया है –

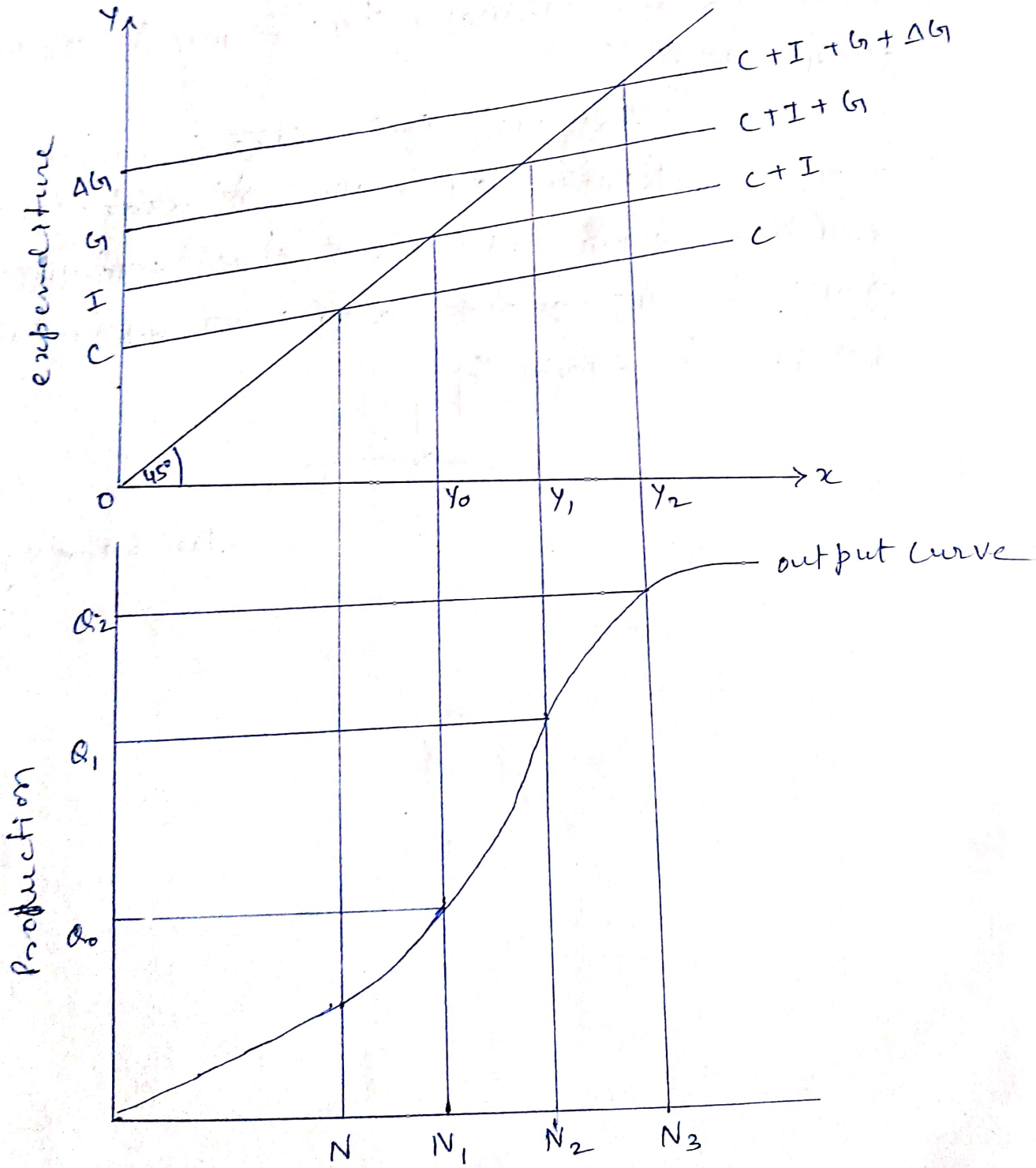

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि AG के बराबर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने से Public expenditure Multiplier effect के कारण आय और उत्पादन को बढ़ा देता है जिससे OY_0 तथा OQ_0 बढ़कर OY_2 तथा OQ_2 हो जाता है। सार्वजनिक व्यय से structural facilities का निर्माण होता है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है।

इसप्रकार यदि सरकार सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक स्वार्थों से अलग होकर सार्वजनिक व्यय करे तो प्रत्येक प्रकार का सार्वजनिक व्यय उत्पादक हो सकता है।

—x—

Dr Sandhya Rani